Statement-II

Proforma proposals sent for Clarification/ Modification

(Rs. in Lakhs)

SI No.	Name of Town	Project Cost
1.	Salaya	81.00
2.	Bhanwad	361.00
3.	Ranavav	55.00
4.	Adityana	56.00
5.	Kutiyana	80.00
6.	Vanthali	149.00
7.	Visavadar	72.00
8.	Khedbrahma	71.00
9.	Kheralu	38.00
10.	Chikhali	75.00
11.	Devgadh-Baria	68.00
	TOTAL	1106.00

दिल्ली में निर्धनों के आवास के लिए धनिकों पर काररोपण

1080. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के "पायोनियर" में "टेक्सिंग रिच फार हाउसिंग पुअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में धनी लोगों से कर-संग्रहण करके निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, और

(ग)यदि हां, तो धनी लोगों की पहचान करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किया है और इस संबध में कुल कितनी धनराशि वार्षिक रूप से एकत्र करने का लक्ष्य हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) गरीबों की आवास अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए, 7 से 9 अक्टूबर, 1996 तक हुए राष्ट्रीय आवास सम्मलेन ने अन्य के साथ-साथ, विलासमय आवास पर कर लगाने की सिफारिश की है । इसीलिए, राज्य सरकार से (जी.एन.सी.टी.डी. को शमिल करते हुए) शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए" आश्रय कर लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया ।

(ग) "आश्रय कर" लागु करने का निर्णय लेना और एतदर्थ मानदंड का निर्धारण करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का काम है । भारत सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली वार्षिक राशि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची

1081. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारी इस समय सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची है,

(ख) इन कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनायी जा रही है ,

(ग) विगत तीन वर्षों में सरकारी मकानों के निर्माण से संबधित अनुमोदित प्रस्तावाओं में किस-किस वर्ग के लिए कितने-कितने मकानों के निर्माण का प्रावधान है, ओर तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या यह सच है कि नये प्रस्तावों के अनुरूप बनाये जा रहे मकानो में टाइप IV और ऊपर के मकान है, यदि हां, तो टाइप III और नीचे के मकानों का निर्माण न किये जाने के कारण है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेस्वरलू) : (क) सामान्य पूल रिहायशी वास के आवंटन हेतु आवेदन प्रति बंधित आधार पर प्रति दो वर्षों के बाद पात्र सरकारी कर्मचारियों से मांगे जाते हैं । आवंटन वर्ष 1.6.98 से 31.12.98 तक दिल्ली में विभिन्न टाइपो के मकानों हेतु 1.7.97 तक कुल 46498 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वर्ष 1997-98 से शुरू हो रही नौवीं योजना के प्रस्तावों में सामान्य पूल रिहायशी आवास स्कीम हेतु 500 करोड. रू.की राशि निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव पेश किया गया है । भारत के विभिन्न शहरों में उपरोक्त योजना अवधि के दौरान लगभग 10,000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है ।